ज़रूरी है सह्याद्री के पर्यावरण को बचाना

भारत डोगरा

हाल ही में (फरवरी 8-10) गोवा के मडकई गांव में पश्चिम घाट (सह्याद्री) की पर्वतमाला की रक्षा के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं व पर्यावरणविदों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में इस क्षेत्र की अनेक गंभीर होती जा रही पर्यावरण समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया व सह्याद्री की रक्षा के लिए प्रयासों को मजबूत करने के सुझाव दिए गए। इस सम्मेलन का आयोजन अपिको आंदोलन ने पीसफुल सोसाइटी व कीस्टोन संस्थाओं के सहयोग से किया था।

सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी तट के साथ-साथ लगभग 1600 कि.मी. तक चलती है। 1,60,000 वर्ग कि.मी. का यह क्षेत्र महाराष्ट्र के धुले ज़िले से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पांच राज्यों में फैला हुआ है - गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।

अपिको आंदोलन के पांडुरंग हेगड़े ने बताया कि देश के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में वर्षा ठीक से हो इसके लिए पश्चिमी घाट का पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह क्षेत्र तो एक तरह से मानसून हवाओं के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। न्यायालयों में पर्यावरण के अनेक महत्वपूर्ण मुकदमों की पैरवी करने वाले वकील ऋत्विक दत्ता ने कहा कि उन्होंने इस तरह के एक क्षेत्र में वन बचाने का प्रयास किया तो विरोधी पक्ष ने कहा कि यह तो ज़िले के मात्र 0.5 प्रतिशत क्षेत्र का वन है। उनका जवाब था कि किसी मनुष्य को गोली मारी जाती है तो वह शरीर के इससे भी कम भाग में लगती है पर पूरा मनुष्य मर जाता है। इसी तरह बहुत संवेदनशील क्षेत्र के पर्यावरण को आहत करोगे तो एक बड़ा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा।

पर्यावरण कार्यकर्ता सेबेशियन रॉड्रिग्स ने कहा कि गोवा में लौह अयस्क व मैंग्नीज़ का खनन इतने अंधाधुंध ढंग से किया जा रहा है कि जल स्रोत व खेत उजड़ रहे हैं, नदियों में मछलियों का जीवन चक्र तहस-नहस हो रहा है। यहां तक कि गोवा के महत्वपूर्ण जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्र में विनाशकारी खनन हो रहा है। कुछ गांवों में तो खनन का असर इतना अधिक है कि जल स्रोतों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग क्षेत्र से आए किसानों व अध्यापकों ने बताया कि गोवा के अनेक गांवों को उजाड़ने के बाद खनन कार्य उनके गांवों की ओर बढ़ रहा है। इन गांवों में काजू, आम व नारीयल की समृद्ध खेती है और वे इसकी रक्षा अवश्य करेंगे।

इस सम्मेलन के दौरान पर्यावरण विनाश के विभिन्न पक्षों पर अलग-अलग समूह बनाए गए। उन्होंने अपने-अपने विषय पर रिपोर्ट तैयार की और इनकी चर्चा पूरे सदन में की गई।

पांडुरंग हेगड़े ने बताया कि जलवायु बदलाव के संकट के कारण कुछ सदाबहार वनों में अब पतझड़ी वनों जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उनके अपने जिले उत्तर कन्नड़ में जहां 1500 वर्षों से इलायची, काली मिर्च, सुपारी, नारीयल, केले की मिश्रित समृद्ध खेती हो रही है, अब बदलते मौसम में इसे जारी रखना कठिन हो रहा है।

कुछ किसानों ने कहा कि चाहे वर्ष में कुल वर्षा पहले जितनी ही हो, पर उसका वर्ष भर में वितरण बहुत असमान होता है। वर्षा के दिन कम हो जाते हैं, वर्षा कम दिनों में केन्द्रित हो जाती है। इससे कृषि की बहुत क्षति हो रही है।

सामाजिक कार्यकर्ता सिबल ने बताया कि केरल के अट्टापाडी क्षेत्र में जब उनके पूर्वज बसे तो वन आधारित जीविका की कमी नहीं थी। पर जब सरकार ने प्राकृतिक वनों को काटने की अनुमति दे दी व इसके स्थान पर औद्योगिक महत्व के प्लांटेशन लगा दिए तो हमारी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। यह सब आदिवासी विकास के नाम पर किया गया मगर आदिवासियों से पूछा तक नहीं गया कि इससे उनका विकास होगा या विनाश।

बी.आर. हिल्स के सोलिगा समुदाय के साथ काम करने

वाले अनुसंधानकर्ता नितिन राय ने बताया कि समुदाय को नज़दीक से जानने पर एहसास हुआ कि उनके लघु वनोपज लेने के तौर-तरीके या जंगल के थोड़े से क्षेत्र में आग लगाने की प्रथा सह्याद्री वन को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। मगर अधिकारी उनकी परंपरागत समझ को जानने-समझने का प्रयास ही नहीं करते। सोलिगा प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि उनके तौर-तरीकों को आज़माया जाए तो लैंटाना के नियंत्रण और वन्य जीवों के पनपने में सफलता मिल सकती है।

कुछ वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि पर्यावरण पर परियोजनाओं के असर के अध्ययनों में विस्तृत व निष्पक्ष अध्ययन नहीं किया जा रहा है। जल्दबाज़ी में कुछ एकपक्षीय जानकारी एकत्र कर किसी तरह परियोजना का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ऋत्विक दत्ता ने कहा कि विशेषकर पर्यावरण पर खनन के असर सम्बंधी आकलन बेहद जल्दबाज़ी में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं व अन्य कार्यों के लिए वन भूमि न्यौछावर करने की बढ़ती गति बेहद चिंताजनक है।

सम्मेलन के समापन भाषण में सुन्दरलाल बहुगुणा ने पश्चिमी घाट बचाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जब समाज में व्यापक बदलाव आएगा, भोगवादी सोच के स्थान पर सादगी-संतोष की सोच को महत्व मिलेगा, तभी पर्यावरण रक्षा की बुनियाद तैयार होगी। पश्चिम घाट रक्षा का ऐसा अगला सम्मेलन वर्ष 2010 में नीलगिरि पर्वतमाला क्षेत्र में ऊटी के नज़दीक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। ***(स्रोत फीचर्स)***